

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या जी-2-573/दस-2009-216-79
लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय-बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शर्तों का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी 2-2017/दस-2008-216-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य कराया गया है। संदर्भगत अवकाशों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शर्तें निम्नवत् हैं :-

बाल्य देखभाल अवकाश

(I) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(II) बाल्य देखभाल अवकाश उपाजित अवकाश की भांति माना जायेगा और उसी तरह स्वीकृत किया जायेगा।

(III) उपाजित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

(IV) बाल्य देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपाजित अवकाश अवशेष न हो।

दत्तक ग्रहण अवकाश

(1) ऐसे महिला राजकीय सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी। प्रसूति अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की बड़ी हुई अवधि का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रसूति अवकाश का उपभोग कर रही थी।

(2) महिला सरकारी सेवक को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो।

(3) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आवेदन किया जाता है, तो कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुये अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े, निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा :-

(क) यदि किसी महिला सेवक को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त एक वर्ष तक की अवधि के अवकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगा :-

(व) दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु एक माह से कम होने पर एक वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(उ) बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु सात माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ज) बच्चे की आयु नौ माह या अधिक परन्तु दस माह से कम होने पर तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेख के नाम नहीं लिखा जायेगा।

2-जिन महिला कर्मचारियों को शर्तों के अभाव में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है उनके बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को उन्हें देय उपाजित अवकाश में परिवर्तित माना जायेगा।

3-शासनादेश संख्या जी-2-2017/दस-2008-217-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4-उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

5-संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या जी-2-573(1)/दस-2009-216-79, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3-सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 6-वित्त पद माप दण्ड निर्धारण अनुभाग।

आज्ञा से,
वी० एन० दीक्षित,
सचिव।

J-1716
19.12.08

8- प्रसूति अवकाश 18

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79
लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79, दिनांक 04-6-1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमत्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनों व्यवस्थाएँ लागू की गयी संतानों के मामलों में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-6-1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 10 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमत्य कराये जाने की सहानुभूति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थाएँ (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) लागू की गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणोत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

4- उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

5- उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे।

6- सांगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

अनुप मिश्र
(अनुप मिश्र)
प्रमुख सचिव

सेवा में,
संगत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

1952
X
III A
X
अपर पुलिस महानिदेशक
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।
16/12/08

श्री विभागाध्यक्ष

संख्या-जी-2-2017(1)/दरा-2008-216/79, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, लखनऊ।
- 7- राचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

अध्याय 13 प्रसूति अवकाश

उत्तर प्रदेश मूल नियम 101 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम

153—किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह अस्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण दिनों पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनांक न। आहरित कर रही हो विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा किये इस विधित शक्ति प्रयोजित की जाये निम्नलिखित के अधीन रखते हुए, स्वीकृत किया जा सकता—

1—प्रसूति अवकाश के दिनों में, प्रसूति अवकाश अवधि अथवा प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास तक हो सकती है।

परन्तु ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।—

परन्तु यह भी कि यदि महिला सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा भले ही उसे ऐसा अवकाश अन्यथा अनुमत्त हो। फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाये या विकलांग हो जाये तो उसे अपवाद के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमत्त नहीं होगा। जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत मिलने पर प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्षों की अवधि व्यतीत न हो जाये।

2. गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत प्रायः 12 सप्ताह पूर्व प्रसूति अवकाश की अवधि सम्बन्धित महिला सरकारी सेवक जीवित बच्चों की प्रसूति का स्थान दिये निम्न शर्तों के अन्तर्गत पर प्रसूति अवकाश तक हो सकता है, बशर्त कि उन दिनों के अन्तर्गत प्रायः 12 सप्ताह पूर्व प्रसूति अवकाश सम्बन्धित प्रमाण हो।

टिप्पणी : 1—दिनांक 15/1/1979

टिप्पणी : 2—सर्वेक्षण के दिनांक में, जिस पर कानून के अधीन राज्य सेवा अधिनियम, 1948 के उपबन्ध लागू हैं, इस नियम के अधीन देय अवकाश केवल से उक्त अधिनियम के अधीन सामान्य अवधि के लिए अनुमत्त प्रायः की व्यवस्था को ध्यान में रखा जायेगा।

टिप्पणी : 3—वर्ष का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन उक्त सेवा गणराज्य का सामान्य समापन का अधिकार है।

शायददेश सं० सी-4-1205/दस/81 216/1979 दिनांक : जुलाई 1981 द्वारा कानून सामान्य अनुभाग-4 के अन्तर्गत नियम सं० 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसूति किये जो निम्नलिखित हैं :—

शायददेश सं० सी-4-1753/दस 73-2 6-65,टी० सी०, 1 दिनांक 20 जून, 1978 द्वारा महिला सरकारी सेवकों को स्वीकार किये जाने वाले प्रसूति अवकाश संबंधी कानूनों का उद्धार किया गया है और विधायक संशोधन, सं० 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसारित किये गये हैं। उक्त आदेशों और नियमों के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के अधीन रखते हुए महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

1. अधिनियम सं० सी-4-484/दस-90-216-79 दिनांक 3-5-1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

2—अपील करने का एक कारण यह है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप, दिनांकित 20 जून, 1978 के अनुक्रम में राजपत्रा महाद्वय के अंतर्गत यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो से अधिक पत्रों जीवित हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही उसे अन्यथा ऐसा अवकाश देना हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक को जीवित दोनों सन्तानों में से कोई सन्तान जन्म से ही विकलांग/अपंगु हो अथवा बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाये तो ऐसी स्थिति में उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एक और पत्रा होने तक प्रसूति अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

3—उक्त आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इससे पहले वर्तमान नियमों के अंतर्गत प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

154. प्रसूति छुट्टी की छुट्टी के लंबे के नामे नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है किन्तु प्रसूति छुट्टी के क्रम में प्रार्थित कोई भी छुट्टी तभी स्वीकृत की जा सकती है जब प्रार्थना-पत्र के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी 1—प्रसूति छुट्टी के क्रम में छुट्टी देने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाली किसी महिला राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह उन समस्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के समान जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी का लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं, सहायक नियम 89-92 के अनुसार किसी चिकित्सा समिति का आधारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर, जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सहायक अधिकारी द्वारा सहायक नियम 93 के अधीन उसे छूट न दे दी जाये।

टिप्पणी 2—प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी नवजात शिशु की बीमारी की दशाओं में इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी, प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देख-भाल की आवश्यकता है और शिशु के मूल उत्तरी उपस्थिति नितांश आवश्यक है।

टिप्पणी 3—अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि उत्तरी निवृत्ति जाते रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind, but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted only if the request is supported by a medical certificate.

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind.

Note 1. A female gazetted government servant applying for grant of leave in continuation of maternity leave, should, like all gazetted government servants applying for leave on medical certificate produce the required certificate from a medical committee in accordance with Subsidiary Rules 89-92, unless this requirement is relaxed under Subsidiary Rule 93 by the authority competent to grant leave.

Note 1. Deleted.

स्तम्भ 1

स्तम्भ 2

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.

□